3

प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा कर रही छग सरकार

5

भारतीय राजनीति का सशक्त मेल

7

दिव्यांग दिवस पर स्वावलंबन का संदेश

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 31 प्रति सोमवार, 8 दिसंबर 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

छत्तीसगढ़ में मोस्ट वॉन्टेड नक्सली हिडमा के एनकाउंटर से उठे सवाल

हिडमा ढेर, लेकिन रहस्य गहराए, क्या साजिश के तहत हुआ एनकाउंटर?

मृत से ज्यादा मूल्यवान था आत्मसमर्पित हिडिमा

गृहमंत्री विजय शर्मा ने आलाकमान को इम्प्रेस करने के चक्कर में देश का करवाया नुकसान

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

18 नवंबर को लाल आतंक का सबसे दुर्दांत शख्स माडवी हिडिमा उर्फ देवा मारा गया। छत्तीसगढ़ में मोस्ट वॉन्टेड नक्सली और नक्सली संगठन की रणनीतिक रूप से सक्रिय कमांडर हिडमा के एनकाउंटर ने राज्य की कानून–व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन अभियान और पुलिस–प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लंबे समय से राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बने हिडमा की मौत को एक बड़ी सफलता के रूप में पुलिस ने प्रस्तुत किया, लेकिन इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी, तथ्यगत शंकाओं और गोपनीय परिस्थितियों ने इस एनकाउंटर के पीछे की वास्तविकता पर बहस को जन्म

दिया है। हिडमा लंबे समय से नक्सली गतिविधियों की मुख्य समन्वयक माना जाता रहा है। कई जिलों में उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, विस्फोटक निर्माण, पुलिस बलों पर घात लगाकर हमला सहित कई गंभीर मामले दर्ज थे। ऐसे में उसकी मौत पुलिस के लिए उपलब्धि मानी जा सकती है। परंतु यह घटनाक्रम इतना सीधा नहीं रहा। प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी कि पुलिस को फायर करना आवश्यक हो गया? यदि गिरफ्तारी संभव थी तो उसे जिंदा पकड़ने का विकल्प क्यों नहीं अपनाया गया? गोली कमर के ऊपर वाले हिस्से में क्यों दागी गई, चर्चा का विषय बना हुआ है। आमतौर पर आत्मसमर्पण की स्थिति में पुलिस घातक हिस्सों पर गोली नहीं चलाती, बल्कि ऐसी जगह फायरिंग करती है जहाँ जान बच सकती है। हिडिंबा को जिस स्थान पर गोली लगी, उसने परिस्थितियों को और संदिग्ध बना दिया। सूत्रों की माने तो हिडिमा तेलंगाना में आत्मसमर्पण करने वाला था। बस्तर आई जी सुन्दराज ने हिडिमा को छत्तीसगढ में आत्मसमर्पण के लिए तैयार भी कर लिया था पर शायद प्रदेश के गृहमंत्री यह नहीं चाहते थे। (शेष पेज 2 पर)

मध्यप्रदेश में पहली बार हुई जनसंपर्क विभाग की कलम बंद हड़ताल

गणेश जायसवाल की पदस्थापना से विभागीय मंत्री की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों में समय–समय पर विरोध और असंतोष की आवाजें उठती रही हैं, लेकिन जनसंपर्क विभाग का वातावरण सामान्यतः शांत और प्रशासनिक अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में पहली बार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया गया कलम बंद आंदोलन न केवल असामान्य है, बल्कि यह प्रशासनिक कार्यप्रणाली के भीतर चल रहे गहरे असंतोष की ओर संकेत भी करता है। विरोध की जड़ एक ही है नर्मदापुरम में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गणेश जायसवाल की जनसंपर्क विभाग में "अपर संचालक" पद पर पदोन्नति और पदस्थापना। विभाग इसे अपने अधिकार क्षेत्र में सीधा हस्तक्षेप मान रहा है। निश्चित ही इस निर्णय पर विभागीय मंत्री की कार्यप्रणाली पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। जबकि देखा जाये तो वर्तमान आयुक्त दीपक सक्सेना विभाग को बेहतर संभाल रहे हैं। इस तरह से अनावश्यक फेरबदल से माहौल ही खराब होता है।

गणेश जायसवाल की पदस्थापना से फंस गये मुख्यमंत्री

जबसे दीपक सक्सेना ने जनसंपर्क विभाग का दायित्व संभाला है तबसे विभाग की कार्यप्रणाली बेहतर चल रही है। लेकिन जैसे ही विभाग में गणेश जायसवाल की इंट्री होती है पूरे विभाग का माहौल खराब हो जाता है और कलम बंद हड़ताल तक हो जाती है। यहां सवाल उठता है कि जब जनसंपर्क विभाग सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर अन्य विभाग से लाकर दूसरे अधिकारी को बिठाने की क्या जरूरत पड़ी। (शेष पेज 3 पर)

समृद्ध उत्तराखंडः पुष्कर सिंह धामी की संकल्पना और हर नागरिक का सपना

-विजया पाठक

उत्तराखंड के लिए "समृद्ध उत्तराखंड" सिर्फ कोई नारा नहीं, बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक दृष्टि है जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न केवल मौखिक रूप में व्यक्त किया है, बल्कि इसके लिए भारी निवेश, नीतिगत सुधार और विकास-परियोजनाओं का खाका खींचा है। धामी सरकार के तहत लगभग 2 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाएँ राज्य में चल रही हैं। ये परियोजनाएँ चाहे वो रेल, सड़क, हवाई कनेक्टिविटी, स्मार्ट-सिटीज, पर्यावरण-स्मार्ट योजनाएँ हों या पर्यटन एवं हिमालयी क्षेत्रों के लिए बुनियादी सुविधाएँ उत्तराखंड को देश के अग्रिम राज्यों की कतार में खड़ा करने की दिशा में हैं। इसी कड़ी में, 2025 के रजत-जयंती उत्सव के अवसर पर

हाल ही में 142 करोड़ रुपये से अधिक की नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। नगरों में सब्जी, यातायात, पार्किंग, शहरी सुविधाओं के साथ-साथ देहरादून जैसे शहरों में आधुनिक परियोजनाओं जैसे इलेक्ट्रिक-वाहन चार्जिंग स्टेशन, स्मार्ट-पार्किंग आदि को प्राथमिकता दी गई है। अलग-अलग नीतियों का विस्तार किया जा रहा है ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, MSME, स्टार्ट-अप्स, हरित ऊर्जा, आत्मनिर्भर गांव आदि क्षेत्रों में। राज्य सरकार ने कई नई नीतियाँ बनाई हैं। (शेष पेज 2 पर)

हिडमा ढेर, लेकिन रहस्य गहराए, क्या साजिश के तहत हुआ एनकाउंटर?

(पेज 1 का शेष)

हिडिमा जैसे दुर्दांत नक्सली के आत्मसमर्पण के बहुत मायने निकल सकते थे:

- देश भर में लाल आतंक का नेटवर्क एक झटके में टूट जाता।
- पैसों और हथियारों से नक्सल नेटवर्क की कौन मदद करता था।
- पिछले 25 सालों में माडवी हिडिमा उर्फ देवा द्वारा मारे गए 150 से ऊपर फोर्सेस के लोगों के पीछे असली व्यक्ति कौन था?
- झीरम घाटी का असली मास्टर माइंड कौन है?
- भारत में नक्सलवाद को चलाने वाले किरदार कौन है?
- बड़ा सवाल यह है कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या सिर्फ आलाकमान के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए एनकाउन्टर करवाया या इसके पीछे कोई साजिश थी?
- क्या हिडिमा के आत्मसमर्पण करने से बस्तर के आदिवासी हमेशा के लिये लाल आतंक से दूर चले जाते?

आंध्रप्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर संदेह

चर्चा है कि आंध्र पुलिस ने इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ रेड्स चलाईं. इन रेड्स में कृष्णा, एलुरु, काकीनाडा, एनटीआर विजयवाड़ा और कोनसीमा जिलों में छिपे माओवादियों को ढूंढ-ढूंढकर पकड़ा गया। कुल 50 माओवादी कैडर गिरफ्तार किए गए, जो अपने आप में बेहद बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। सुकमा इलाके में जिस माओवादी कमांडर हिडमा की पत्नी और उसके साथियों का एनकाउंटर हुआ, वह सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है. ऑपरेशन के दौरान जवानों ने घने जंगलों में छिपे नक्सलियों को घेर लिया, जिसके बाद दोनों ओर से जोरदार फायरिंग हुई और इसमें हिडमा की पत्नी समेत कई नक्सली ढेर हो गए. मौके से हथियार, गोला-बारूद और नक्सली सामग्री भी बरामद की गई. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस कार्रवाई से माओवादी संगठन की रीढ़ और कमजोर पड़ गई है, क्योंकि ये सभी हिडमा के भरोसेमंद और सक्रिय कैडर माने जाते थे।

समर्पण का विकल्प कितना मजबूत था?

चर्चा यह भी है कि हिडमा बीते कुछ महीनों से आत्मसमर्पण के बारे में बातचीत कर रहा था या सुराग तलाशने वाली एजेंसियों के संपर्क में था। इस तथ्य की आधिकारिक पुष्टि न तो पुलिस ने की और न ही राज्य के गृहमंत्रालय ने। लेकिन नक्सल विरोधी अभियानों से जुड़े लोगों के हवाले से यह दावा सामने आया कि उसके आत्मसमर्पण की संभावना तेजी से बढ़ रही थी। यही बिंदु आलोचना का केंद्र है यदि हिडमा जीवित पकड़ा जाता, तो नक्सली नेटवर्क के बड़े हिस्से की जानकारी उजागर हो सकती थी। हथियार सप्लाय चेन, प्रशिक्षण तंत्र, वित्तीय नेटवर्क, स्थानीय समर्थन और माओवादी नेतृत्व की गतिविधियों का अंदरूनी डेटा मिल सकता था। इसी कारण आलोचना के स्वर बुलंद हुए कि कहीं उद्देश्यपूर्ण ढंग से उसे जिंदा न रखने का निर्णय तो नहीं लिया गया?

राजनीतिक बयानबाजी और आरोपों की श्रृंखला

एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले प्रमुख नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सबसे आगे रहे। उन्होंने पूछा कि अगर हिडमा को घेरा गया था, तो उसे आत्मसमर्पण का अवसर क्यों नहीं दिया गया? दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि पुलिस ने गोली मारी, तो गैर–घातक हिस्सों में क्यों नहीं मारी? उनका तर्क है कि सूचना देने, नेटवर्क उजागर करने और नक्सल संगठन की रणनीतियों का पर्दाफाश करने वाले डेटा तक पहुंचने का अवसर मुख्यमंत्री और केंद्रीय एजेंसियों ने खो दिया। यहाँ तक आरोप लगे कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सामने उपलब्धि प्रदर्शित करने के लिए छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा द्वारा इसे एक 'त्वरित सफलता' के रूप में पेश किया गया। विपक्ष दावा कर रहा है कि यह एनकाउंटर नक्सल विरोधी नीति की रणनीति से ज्यादा राजनीतिक लाभ का साधन बन गया।

पुलिस का पक्ष और सरकारी दलीलें

दूसरी ओर पुलिस और गृह विभाग अपनी दलीलों में यह कह रहे हैं कि सुरक्षा बलों पर उस समय हमला हुआ। जवाबी फायरिंग में हिडमा मारा गया। कोई आत्मसमर्पण जैसी परिस्थिति उस समय उपलब्ध नहीं थी, ऑपरेशन जोखिमपूर्ण था और त्वरित कार्रवाई आवश्यक थी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, क्षेत्र जंगल, पहाड़ी ढलानों और घने झाड़ियों वाला था, जहां टकराव की स्थिति में कोई रणनीतिक वार्ता संभव नहीं हो सकती थी। सुरक्षा विशेषज्ञों का मत है कि नक्सल संगठन में हिडमा की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वह नए युवाओं की भर्ती में सक्रिय था, हथियारों की खेप और विस्फोटक सामग्री के परिवहन में सहयोगी था, महिला विदेशी मीडिया से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। इन बिंदुओं से स्पष्ट है कि उसका जीवित रहना नक्सल संगठनों के लिए रणनीतिक लाभ बना हुआ था। एनकाउंटर के बाद बड़ा प्रश्न यही है कि क्या पुलिस ने एक ऐसे अवसर को गंवा दिया, जहाँ जमीन–स्तर पर गहरी सूचनाएँ मिल सकती थीं? यह वही प्रश्न है जिसने इस पूरे मामले को एक गहन बहस का विषय बना दिया। यदि कोई उच्च स्तरीय पूछताछ होती, तो संभवतः उस नेटवर्क तक पहुँचा जा सकता था जो दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसी घटनाओं का आधार बनता रहा है। देखा जाये तो स्पष्ट तथ्य अब तक सार्वजनिक नहीं हैं, इसलिए आवश्यक है कि स्वतंत्र जाँच समिति का गठन हो, ऑपरेशन के वीडियो डेटा या वायरलेस रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जाए, एसेस्कलेशन मॉडल का अध्ययन हो। हिडमा की मौत से प्रशासनिक और सुरक्षा लाभ तो दिखाई देते हैं, परंतु इसके साथ यह भी तथ्य है कि उसकी गिरफ्तारी राज्य और केंद्र की संयुक्त एजेंसियों को एक महत्वपूर्ण मोड़ दे सकती थी। इस एनकाउंटर के पीछे की प्रक्रिया, निर्णय–समय, परिस्थितियाँ और कमांड–स्ट्रक्चर अभी भी धुंध में छिपे हुए हैं। मामले को सिर्फ सफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि नक्सल उन्मूलन रणनीति की सामरिक और दीर्घकालिक दृष्टि से भी परखा जाना चाहिए। यदि इस घटना से राजनीतिक लाभ जुटाया गया, तो यह नक्सल समस्या के मूल समाधान की दिशा में बाधा बन सकता है। दूसरी ओर, यदि परिस्थितियाँ सचमुच उतनी ही जोखिमपूर्ण थीं जितना पुलिस दावा कर रही है, तो एनकाउंटर की कार्रवाई को सुरक्षित रणनीतिक निर्णय भी माना जा सकता है।

छत्तीसगढ़ में मार्च 2025 तक होना है नक्सलवाद का खात्मा

कुख्यात नक्सली माड़वी हिड़मा को सुरक्षाबलों ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। माड़वी हिड़मा की मौत देश में नक्सलवाद के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है और इससे नक्सलियों की सैन्य क्षमताएं कमजोर होंगी। हाल के वर्षों में देश में हुई हर बड़ी नक्सली घटना के पीछे माड़वी हिड़मा का ही दिमाग माना जाता है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल सुरक्षाबलों ने छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर हुई एक मुठभेड़ में देश के सबसे खतरनाक और वांछित नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा को ढेर कर दिया। माओवादियों को यह हाल के वर्षों में लगा सबसे बड़ा झटका है और दावा किया जा रहा है कि माड़वी हिड़मा की मौत के बाद अब देश में नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है।

कौन था माड़वी हिड़मा?

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जन्में माड़वी हिड़मा ने 16 साल की उम्र में ही हथियार उठा लिए थे और बतौर कैडर शुरुआत करके माड़वी हिड़मा बीते दो दशकों में प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) में कई अहम पदों पर रहा। हिड़मा कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था और उस पर सरकार ने एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। माड़वी हिड़मा सीपीआई माओवादियों की बटालियन नंबर एक का कमांडर था, जो नक्सलियों की सबसे खतरनाक सैन्य टुकड़ी मानी जाती है। हिडमा दंडकारण्य क्षेत्र के घने जंगलों में रहता था और उसे अबूझमाड़ और सुकमा-बीजापुर के वन क्षेत्रों की काफी जानकारी थी। यही वजह थी कि कई कोशिशों के बाद भी हिडमा लंबे समय तक सुरक्षाबलों से बचता रहा। हिडमा फिलहाल बस्तर दक्षिण इलाके में सक्रिय था।

दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ पर हमले समेत कई बड़े हमलों का था मास्टरमाइंड

हिड़मा कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल के वर्षों के अधिकतर बड़े नक्सली हमलों में उसकी संलिप्तता था फिर चाहे वो साल 2010 में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ पर हुआ हमला हो, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवानों बलिदान हुए थे या फिर दरभा घाटी में झीरम घाटी का हमला, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूरे कांग्रेस नेतृत्व को खत्म कर दिया गया था। साल 2017 में सुकमा में हुए दो हमलों, जिनमें 37 जवानों की मौत हुई थी और 2021 के बीजापुर में तर्रेम हमले में भी माड़वी हिड़मा का नाम सामने आया था। सुरक्षाबलों का दावा है कि अप्रैल 2025 में कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर हुई मुठभेड़ में हिड़मा बाल-बाल बच गया था। उस मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए थे। कुख्यात नक्सली माड़वी हिड़मा को सुरक्षाबलों ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। माड़वी हिड़मा की मौत देश में नक्सलवाद के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है और इससे नक्सलियों की सैन्य क्षमताएं कमजोर होंगी। माओवादियों को यह हाल के वर्षों में लगा सबसे बड़ा झटका है और दावा किया जा रहा है कि माड़वी हिड़मा की मौत के बाद अब देश में नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है।

नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरू

बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज पी का कहना है कि माड़वी हिड़मा की मौत नक्सलवाद के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि कई कुख्यात माओवादी हाल के समय में ढेर हो चुके हैं और कई मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। अब बाकी बचे नक्सली कमांडरों से भी आत्मसमर्पण की अपील की जाएगी और जो अभी भी हिंसा के रास्ते पर चलेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिडमा की मौत से बस्तर क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। सरकार ने साल 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य तय किया और माड़वी हिड़मा की मौत उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि हिडमा की मौत के साथ ही देश में नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है।

समृद्ध उत्तराखंडः पुष्कर सिंह धामी की संकल्पना और हर नागरिक का सपना

(पेज 1 का शेष)

ग्राम-गणतंत्र से आत्मनिर्भर गांव तक

उत्तराखंड में युवाओं का पलायन हमेशा समस्या रही है। धामी सरकार इस समस्या को पहचानते हुए, "आत्मनिर्भर गांव, समृद्ध उत्तराखंड" की दिशा में काम कर रही है। हर जनपद में दो-दो गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने की योजना है। कृषि, बागवानी, स्थानीय उद्योग, MSME, स्टार्ट-अप जैसे विकल्पों को मजबूत करके न केवल रोजगार देना बल्कि युवा शक्ति को प्रदेश में बनाए रखना धामी की प्राथमिकता रही है। यह दृष्टि सिर्फ बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं: किसानों, छोटे व्यापारियों और युवाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, स्वरोजगार व जीवन बेहतर बनाए जाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

शिक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण और आधुनिकता

शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन हो रहा है; सरकार ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल सुविधाओं, वर्चुअल-क्लासेस, आधुनिक शिक्षण के साधन लाए हैं। ऊर्जा और हरित विकास के क्षेत्र में भी कदम उठाये गए सौर ऊर्जा, हरित ऊर्जा योजनाएँ, पर्यावरण-स्मार्ट प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जा रही है। इन प्रयासों के माध्यम से धामी सरकार ने यह संकेत दिया है कि उत्तराखंड की विकास यात्रा सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पर्वतीय, गांव, ग्रामीण इलाके, प्राकृतिक संसाधन सबका समग्र विकास लक्ष्य है।

सांस्कृतिक-परंपरा, सामाजिक एकता और स्थिरता

"समृद्ध उत्तराखंड" की संकल्पना में आधुनिकता के साथ राज्य की सांस्कृतिक-धरोहर, सामाजिक सौहार्द, जन-संरचना की रक्षा और सामूहिक पहचान का भी ध्यान रखा गया है। धामी सरकार ने कानून सुधार, सामाजिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था जैसे पहलुओं को विकास के बराबर प्राथमिकता दी है। पर्यटन, हिमालयी संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक धरोहर सब कुछ विकास की डोर से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य राज्य को केवल आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय रूप से सशक्त बनाना है। केंद्र के निवेश, बुनियादी ढांचे, नीतियों व योजनाओं के बीच असली सफलता इस बात पर टिकी है कि हर नागरिक, हर गांव, हर युवा उसका हिस्सा बने। धामी की संकल्पना यही है, विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि जीवन स्तर, रोजगार, सम्मान, सुरक्षा, अवसर और भविष्य-निर्माण में हो। पुष्कर सिंह धामी का "समृद्ध उत्तराखंड" एक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और मानवीय दृष्टि का अभिप्राय है जिसमें शहर, गाँव, पर्वत, मैदान, युवा, बुजुर्ग सभी के लिए विकास, अवसर और सुगम जीवन है। अगर यह संकल्प जमीन पर सही तरीके से लागू हुआ निवेश, परियोजनाएँ, नीतियाँ, योजनाएँ सब मिलकर तो उत्तराखंड न केवल हिमालय की गोद में बसे राज्य के रूप में, बल्कि आत्मनिर्भर, सशक्त, विकसित, समृद्ध व संतुलित विकास का मॉडल बनकर उभरेगा। "समृद्ध उत्तराखंड" केवल एक सपना नहीं रहेगा, बल्कि हर नागरिक के लिए आज, कल और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवंत वास्तविकता बनेगा।

प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा कर रही छत्तीसगढ़ सरकार : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

1073 हितग्राहियों को सौंपी नये आवास की चाबी

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का ध्येय है कि हर घर में पक्का मकान, शौचालय, शुद्ध पेयजल और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ पहुंचे। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए हमारी सरकार जनता के हित में वचनबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बने 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। सरकार बनने से पहले प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी में जो वादे किए गए थे, उन्हें हम एक-एक कर पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम सुहेला में आयोजित कार्यक्रम में 195.26 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 1073 हितग्राहियों को आवास की चाबी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत तीन हजार महिलाओं को गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना अंतर्गत पाँच हजार किसानों को अधिकार अभिलेख तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को सामग्री और राशि के चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी हो रही है। तेंदूपत्ता संग्रहण की दर बढ़ाकर प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये कर दी गई है। किसानों को दो वर्ष का बकाया बोनस भी प्रदान किया जा चुका है। महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ बड़ी संख्या में महिलाओं को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत हर घर को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में बड़ी मात्रा में सब्सिडी भी मिल रही है, इसलिए अधिक से अधिक लोग अपने घरों में सोलर पैनल स्थापित कर लाभ उठाएँ। उन्होंने जिले में प्रशासन की 'हम होंगे कामयाब' पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार प्रशिक्षित कर उनके बेहतर भविष्य के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे अब तक 500 से अधिक युवाओं को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम के दौरान सुहेला में नवीन महाविद्यालय की स्थापना, तिल्दा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, बलौदाबाजार में शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भवन एवं नवीन व्यावसायिक परिसर का निर्माण करने की घोषणा की। उन्होंने जिले के 50 धान उपार्जन केंद्रों में किसानों के लिए 10-10 लाख रुपये की लागत से शेड निर्माण तथा सुहेला तिगड्डे में तीनों सड़कों पर एक-एक किलोमीटर तक डिवाइडर निर्माण एवं लाइट लगाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने जिन विकास कार्यों का लोकार्पण किया, उनमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 12.87 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 1073 आवास, तथा लगभग 7.74 करोड़ रुपये की लागत से आमाकोनी, हथबंद, पौसरी, सेम्हराडीह और खपराडीह में निर्मित जल प्रदाय योजनाएँ शामिल हैं। भूमिपूजन के प्रमुख कार्यों में 49.17 करोड़ रुपये की लागत से बलौदाबाजार–रिसदा–हथबंद मार्ग मजबूतीकरण, 20.98 करोड़ रुपये की लागत से बलौदाबाजार के रिसदा बायपास मार्ग, 15.59 करोड़ रुपये की लागत से बलौदाबाजार में इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, 8.60 करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 717 आवास तथा 8.04 करोड़ रुपये की लागत से कोल्हान नाले के पार सुंगेरा एनिकट निर्माण शामिल हैं। कार्यक्रम में 5 करोड़ रुपये से अधिक की हितग्राहीमूलक सामग्री एवं चेक वितरण किया गया। इसमें मुख्य रूप से सायबर फ्रॉड प्रकरण के 27 लाख रुपये की वापसी, श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं में 83 लाख रुपये का वितरण, 8333 छात्रों को 4.25 करोड़ रुपये की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, महिला स्व सहायता समूहों एवं 'सक्षम' योजना अंतर्गत 16 महिलाओं को 25 लाख रुपये, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 10 हितग्राहियों को 9.69 लाख रुपये तथा 'हम होंगे कामयाब' योजना अंतर्गत 60 हितग्राहियों को 6.81 लाख रुपये का भुगतान शामिल है। इस अवसर पर बलौदाबाजार-भाटापारा जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष रायपुर नवीन अग्रवाल, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, महिला आयोग की सदस्य लक्ष्मी वर्मा, जनपद अध्यक्ष सिमगा दौलत पाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

उपार्जन केंद्रों में प्रदेश भर में धान खरीदी सुचारू रूप से जारी

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से जारी है। राज्य के सभी जिलों में खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्रदेश के जशपुर जिले में भी धान खरीदी प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। 3 दिसंबर तक जिले के 46 उपार्जन केंद्रों में कुल 2,628 किसानों से 1,67,246 क्विंटल धान उपार्जित किया जा चुका है। इसके एवज में 39.62 करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों के बैंक खातों में निरंतर हस्तांतरित की जा रही है। धान खरीदी कार्य को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए उपार्जन केंद्रों में टोकन प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण, नमी मापक यंत्र समेत सभी आवश्यक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही पर्याप्त बारदाना, बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी और अन्य आवश्यक प्रबंध भी सुनिश्चित किए गए हैं, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जिला प्रशासन के निरंतर निरीक्षण और मॉनिटरिंग के कारण धान खरीदी कार्य निर्बाध रूप से संचालित हो रहा है। निर्धारित तिथि के अनुसार किसान केंद्रों में पहुंचकर अपना धान बेच रहे हैं और समर्थन मूल्य के माध्यम से उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है।

निःशुल्क साइकिल योजना अंतर्गत 1000 साइकिलों का होगा वितरण

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9वी के 13 विधार्थियों को निःशुल्क साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्षद सुनिल दुबे, स्कूल प्राचार्य ज्योति दुबे, शिक्षक मनीष सोनकिया, हरिओम गौर, जन शिक्षक रामकृष्ण गौर, निशा कैथवास, अभिनव राजपूत उपस्थित थे साइकिल पाने वाले विधार्थियों को कुमकुम तिलक लगाकर अतिथि द्वारा सम्मान किया गया। पार्षद दुबे ने विधार्थियों को शासन द्वारा विधार्थियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और साथ ही यह भी बताया कि विकासखण्ड में 1000 से अधिक साइकिल का वितरण किया जा रहा है, जिसमें नौवीं कक्षा में 638 और छठवीं की 399 विधार्थियों को साइकिल दी जाएगी। विधार्थियों द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया गया।

मध्यप्रदेश में पहली बार हुई जनसंपर्क विभाग की कलम बंद हड़ताल

(पेज 1 का शेष)

अब इस नये फंसाद में विभागीय मंत्री मोहन यादव बुरे फंस गये हैं। जबकि देखा गया है कि विभाग के ही किसी वरिष्ठ अधिकारी को इस पद पर बिठाया जा सकता था जिससे किसी प्रकार का विरोध भी नहीं होता और असंतोष भी नहीं फैलता।

पदोन्नति का आदेश और नियमों पर उठे सवाल

जनसंपर्क विभाग में अधिकारी और कर्मचारियों ने पदोन्नति आदेश को नियमों के विरुद्ध बताया। उनका कहना है कि जनसंपर्क विभाग के संवर्ग में पदोन्नति के स्पष्ट नियम, वरिष्ठता क्रम और विभागीय प्रक्रिया मौजूद है। ऐसे में किसी अन्य संवर्ग विशेषकर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को अपर संचालक जनसंपर्क के पद पर पदोन्नत करना विभागीय अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। अधिकारी-कर्मचारी एकमत होकर कलम बंद हड़ताल पर उतर आए। धीरे-धीरे यह विरोध राज्य भर में फैल गया और जिला स्तर के कार्यालय भी आंदोलन में शामिल होने लगे थे। हालांकि बाद में समझाईश के बाद यह हड़ताल खत्म हो गई। लेकिन आखिर में सवाल यही उठता है कि इतिहास में पहली बार हड़ताल की नौबत कैसे आयी।

ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों की स्पष्ट मांग

मध्यप्रदेश जनसंपर्क अधिकारी संघ ने आयुक्त जनसंपर्क को ज्ञापन सौंपकर साफ कहा है कि यह नियुक्ति विभागीय अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है। यह संवर्ग के अस्तित्व पर सीधा हमला है। आदेश तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा प्रदेश के सभी जिला कार्यालयों में काम ठप रखा जाएगा। ज्ञापन में यह चेतावनी भी दी गई कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो हड़ताल को प्रदेशव्यापी स्तर पर आगे और तेज किया जाएगा, जिससे विभाग का संपूर्ण कामकाज अनिश्चितकाल तक प्रभावित हो सकता है।

इसलिए उभरा इतना बड़ा विरोध? संवर्ग का अस्तित्व संकट में

जनसंपर्क विभाग के अधिकारी लंबे समय से यह मांग उठाते रहे हैं कि विभागीय संरचना, पदोन्नति और नियुक्तियाँ पारदर्शी ढंग से हों। राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी सीधे अपर संचालक स्तर पर लाया जाना उन्हें अपने संवर्ग पर "अतिक्रमण" जैसा लगा।

वरिष्ठता और कैडर नियमों की अनदेखी

जनसंपर्क अधिकारियों का कहना है कि उनके भीतर ऐसे कई अधिकारी मौजूद हैं जो वर्षों से वरिष्ठता सूची में प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में बाहरी अधिकारी की पदोन्नति और तैनाती उनके कैरियर ग्राफ पर सीधा असर डालती है।

विभागीय स्वायत्तता पर आघात

जनसंपर्क विभाग का कार्य बेहद विशिष्ट और विशेषज्ञता आधारित माना जाता है। लेखन, मीडिया प्रबंधन, जनसंपर्क कौशल, संचार मनोविज्ञान, सरकारी योजनाओं की प्रस्तुति आदि इसकी मूल आवश्यकताएँ हैं। अधिकारी-कर्मचारी मानते हैं कि इस विशेषज्ञता की अनदेखी कर निर्णय लेना विभागीय कौशल और प्रोफेशनलिज्म को कमजोर करता है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा क्या यह निर्णय जल्दबाजी में लिया गया?

सूत्रों के अनुसार विभाग के भीतर और राजनीतिक दायरों में यह चर्चा भी है कि फैसले की प्रक्रिया में वरिष्ठ अधिकारियों से उचित परामर्श नहीं लिया गया। जनसंपर्क विभाग में पहले भी बाहरी संवर्ग से पदस्थापना के प्रयास हुए थे, जिन पर बाद में विवाद बढ़ा और सरकार को निर्णय वापस लेना पड़ा। यह मामला अब केवल विभाग का नहीं रहा, यह शासन की निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता और विभागीय स्वायत्तता की कसौटी बन चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि सरकार समाधान का मार्ग अपनाती है या विवाद और गहरा होता है। अब गेंद सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के पाले में है उन्हें तय करना है कि यह केवल एक आदेश का सवाल है या पूरे विभाग के आत्मसम्मान का।

थमा गया था सूचनाओं का प्रवाह

जनसंपर्क विभाग वह धुरी है, जिसके माध्यम से शासन से जनता तक और जनता से शासन तक सूचनाओं का संचार होता है। हड़ताल के कारण प्रेस नोट्स, सरकारी कार्यक्रमों की फोटो–वीडियो रिलीज, मीडिया समन्वय, सोशल मीडिया संचालन और जिला स्तर पर सूचना प्रसारण लगभग बंद हो गई थी। सूत्रों के अनुसार जिस दिन विभाग में काम पूरी तरह ठप था, उसी दिन मुख्यमंत्री और सरकार से संबंधित खबरों को प्रकाशित करवाने की जिम्मेदारी भाजपा के मीडिया सेल ने निभाई। यह स्थिति स्वयं में जनसंपर्क तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। क्या किसी प्रशासनिक निर्णय ने विभागीय तंत्र को इतना कमजोर कर दिया है कि काम बाधित होते ही वैकल्पिक प्रणाली सक्रिय करनी पड़ रही है? साथ ही इस मामले का एक और पहलू है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं जनसंपर्क विभाग के प्रभारी मंत्री हैं। अपने ही विभाग के अधिकारियों का सामूहिक विरोध, काम बंद कर देना और विभाग का ठप्प होना यह स्थिति मुख्यमंत्री की प्रत्यक्ष निगरानी वाले विभाग में असाधारण मानी गई।

सम्पादकीय

मोदी–पुतिन की मुलाकातः एक नए विश्व-दृष्टिकोण का संकेत

जब नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन ने दिसंबर 2025 में दिल्ली में मुलाकात की वह केवल दो देश के बीच राजनयिक वार्ता नहीं थी, बल्कि एक व्यापक वैश्विक संदेश था। यह संदेश दिखाता है कि 21वीं सदी के अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध अब शक्ति-पक्षपात और द्विरायीयता की बजाय बहु-ध्रुवीय व्यवस्था, रणनीतिक स्वायत्तता, कूटनीतिक अस्मिता और साझेदारी की ओर अग्रसर हो रही है। इस शिखर बैठक में दोनों देशों ने 2030 तक वार्षिक व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य तय किया। तेल-गैस या हथियार तक सीमित नहीं समझौते उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, शिपिंग, स्वास्थ्य, जहाज निर्माण और उच्च-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों तक फैले हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यह भारत और रूस दोनों के लिए "स्व-निर्भरता और "आर्थिक विविधीकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है वैश्विक अर्थव्यवस्था विशेष रूप से पश्चिमी दबाव और एकाधिकारवाद के दबाव में है, ऐसे में यह साझेदारी स्थिरता, वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाएं और विकास-निर्भरता प्रदान कर सकती है। दोनों नेताओं ने सिविल न्यूक्लियर सहयोग, रक्षा, समुद्री लॉजिस्टिक्स, नौवहन, मानव संसाधन और संभावित मुक्त व्यापार समझौते जैसे कई विषयों पर सहमति जताई। पुतीन ने स्पष्ट किया कि रूस भारत को ऊर्जा आपूर्ति में समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा चाहे अंतरराष्ट्रीय दबाव हो या न हो। यह पहल संकेत देती है कि भारत पश्चिम के दबाव में दबने के बजाय अपनी विदेश नीति और सामरिक निर्णयों में स्वायत्त रहना चाहता है: जरूरी संसाधन, रक्षा-साझेदारी और ऊर्जा-सुरक्षा के लिए रूस जैसे भरोसेमंद साझेदारों की ओर रुख करना।

पश्चिम-केंद्रित वैश्विक ढांचे में परिवर्तन हो रहा है। भारत-रूस की यह साझेदारी उस परिवर्तन की देहरी पर है जहाँ देश अपनी अस्मिता, स्व-निर्भर निर्णय-शक्ति और विविध कूटनीतिक रिश्तों को प्राथमिकता दे रहे हैं। यूक्रेन जैसे विवादित अंतरराष्ट्रीय मसलों पर भी, भारत ने स्पष्ट किया कि वह शांति और बातचीत का पक्षधर है, और किसी भी पक्षपात में नहीं फँसेगा। इस प्रकार, मोदी–पुतिन मुलाकात ने दिखाया कि नई कूटनीति शक्ति प्रदर्शन या एकाधिकार की बजाय "साझा हित, विश्वास, बहुपक्षीय संवाद और रणनीतिक संतुलन" पर आधारित हो सकती है। मोदी–पुतिन की हालिया मुलाकात महज एक राजनयिक दौरा नहीं थी यह एक वैश्विक मिस्ट्री कोड की तरह थी, जो संकेत दे रही थी कि विश्व अब एक-ध्रुवीयता से आगे बढ़ रहा है। उस कोड का अर्थ है भरोसा, आत्मनिर्भरता, बहु-मैलिक साझेदारी, और रणनीतिक स्वायत्तता। भारत-रूस की यह साझेदारी न केवल द्विपक्षीय स्तर पर, बल्कि वैश्विक कूटनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में एक नया मॉडल पेश करती है। यह संकेत है उन देशों के लिए जो संविधान, संसाधन, विकास, रक्षा और कूटनीति के बीच संतुलन चाहते हैं। इस प्रकार, मोदी–पुतिन मुलाकात ने पूरी दुनिया को याद दिलाया "नई दुनिया" केवल उन्हीं के लिए है जो बहु-ध्रुवीयता, साझा हित और सामूहिक भरोसे को स्वीकारने के लिए तैयार हैं।

सियासी गहमागहमी

एमपी गजब है, भ्रष्टाचार जायज है !

मध्यप्रदेश विधानसभा में कांग्रेस द्वारा जिस फर्जी अस्पताल-बिल भुगतान के घोटाले को उठाया गया है, वह न सिर्फ एक कानूनी सवाल है, बल्कि सरकार और प्रशासन पर विश्वासघात की व्यंग्यात्मक गहनी भी बनकर चमक रहा है। कल्पना करिए राज्य सरकार गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा का वादा करती है, लेकिन उसी वादे के नाम पर ऐसा फर्जी अस्पताल अस्तित्व में नहीं है, फिर भी करोड़ों रुपये भुगतान कर दिए जाते हैं। ऐसा लगता है मानो नकली अस्पताल के नाम पर 'स्वास्थ्य सेवा' नहीं, बल्कि 'भ्रष्टाचार सेवा' स्थापित कर दी गई हो। कांग्रेस की नसीहत, सवाल और मांगें— जिससे साफ हुआ कि कितनी आसानी से नकली बिल बनाकर पैसा हाथ धोने जैसा खेल खेला जा सकता है- यह लोक-स्वास्थ्य नहीं, बल्कि सरकारी खजाने का मजाक है। उस मजाक की बाजीगरी करने वालों से पूछोः मरीजों के वजूद से नहीं, सिर्फ बकायेदार रसीदों से उनको भुगतान मिला। यदि असली अस्पतालों, मरीजों या स्टाफ की मौजूदगी ही नहीं फिर बिलों की रसीदों के आधार पर करोड़ों रुपए कैसे खाए गए, यह समझना प्रशासन के लिए एक व्यंग्य है। जनता के पैसों को इस तरह 'सर्जरी' दिखाकर काटना, स्वास्थ्य नहीं, सामाजिक विश्वास की मौत है।

कमलनाथ के विकसित प्रदेश के मॉडल को अपना रही भाजपा

क्या खूब! लगता है कि कमलनाथ द्वारा रचे गए "छिंदवाड़ा मॉडल" को गुपचुप तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब बेचने की तैयारी में है। मतलब, अगर राजनीति एक दुकान होती, तो अब विंडो पर बड़े अक्षरों में लिखा होगा "पलटकर बेच रहे हैं वही पुराने वादे -लेकिन नाम बदलकर। वह मॉडल जिसे कभी कांग्रेस ने जनता के भरोसे के साथ सजाया- संवार कर चुनावी कैटलॉग में सजाया था, आज बीजेपी ने उसी फोटो कॉपी को ले लिया है, ऊपर नया लोगो 'बीजेपी' का चस्पा कर दिया। लगता है विकास का पैकेज बेचने वालों का लेबल बदलना अब नई राजनीति की चाल हो गई है। आखिर, वो छिंदवाड़ा जो कभी 'कांग्रेस की धरोहर' रहा, अब 'बीजेपी की विजयगाथा' बनने चला है जैसे कोई फिल्म बार-बार रीमेक होकर दिखाए जा रही हो। जनता पूछेगीः कहानी वही, किरदार बदल गए, परिणाम वही या बस पोस्टर में रंग? अगर विकास मॉडल सिर्फ नारे और पोस्टर तक सीमित रह गया तो यह दिखावा नहीं, धोखा कहलाएगा।

हफ्ते का कार्टून

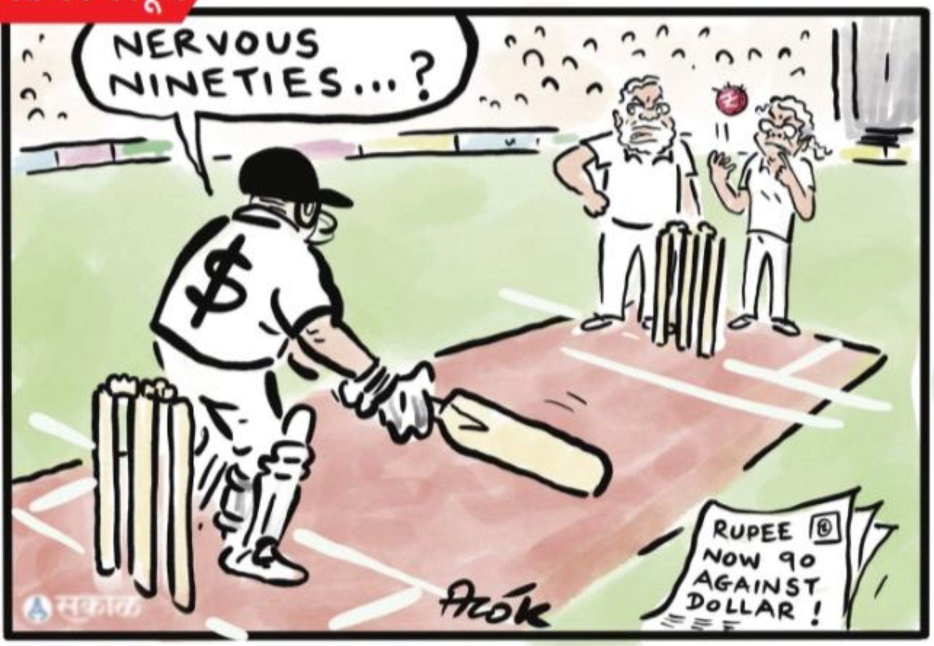

ट्वीट-ट्वीट

संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा - उनका जवाब चौंकाने वाला है।
न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा, और न ही जनता से संवाद।
दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं।
मोदी सरकार की यह जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

आज छिंदवाड़ा में परिवारजनों से मुलाकात की। छिंदवाड़ा के एक-एक व्यक्ति का सुख और दुख मेरा सुख और दुख है।

छिंदवाड़ा की सेवा करना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुफल है।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

शशि थरूर : वैश्विक अनुभव और भारतीय राजनीति का सशक्त मेल

समता पाठक/जगत प्रवाह

भारत की समकालीन राजनीति में कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनकी पहचान केवल राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि विचारक, लेखक और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के दिग्गज के रूप में भी स्थापित है। शशि थरूर ऐसा ही एक नाम है- एक नेता जिनकी यात्रा लंदन से संयुक्त राष्ट्र तक और वहाँ से भारतीय संसद तक विस्तृत है। उनका व्यक्तित्व वैश्विक समझ और भारतीय अस्मिता का अद्भुत संगम है। थरूर का जन्म 9 मार्च 1956 को लंदन में हुआ था। बचपन में उनका परिवार भारत लौट आया और उनका लालन-पालन देश के विविध सांस्कृतिक वातावरण में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी हुई, जिसने उन्हें भारतीय समाज की गहरी संवेदना दी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफंस कॉलेज से इतिहास में स्नातक किया। शिक्षा के प्रति उनकी जिज्ञासा अंतरराष्ट्रीय पटल तक ले गई। अमेरिका के फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यह उपलब्धि उन्होंने मात्र 22 वर्ष की आयु में हासिल की—जो उस समय असाधारण मानी गई।

उच्च शिक्षा के बाद उन्होंने 1978 में संयुक्त राष्ट्र में अपना कैरियर प्रारंभ किया। थरूर ने आरंभिक वर्षों में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) के साथ जिनेवा और बाद में सिंगापुर में सेवा दी। उस दौरान उन्होंने वियतनामी शरणार्थी संकट में महत्वपूर्ण प्रबंधन भूमिका निभाई। 1990 के दशक में शांति स्थापना से जुड़े अभियानों में उनका योगदान उन्हें संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व के केंद्र तक ले गया। 2001 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के संचार व जनसूचना विभाग का अवर-महासचिव नियुक्त किया गया—एक पद जिसने उन्हें वैश्विक संवाद का प्रमुख चेहरा बनाया। 2006 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद की दौड़ में भाग लिया और दूसरे स्थान पर रहे—यह स्वयं अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उनकी प्रतिष्ठा का प्रमाण था। इसके बाद 2007 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से सेवानिवृत्ति ली और राष्ट्रसेवा हेतु भारत लौटने का निर्णय किया।

भारत लौटकर उन्होंने 2009 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उसी वर्ष वे केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और तब से लगातार 2014, 2019 और 2024 में भी वहीं से चुने जाते रहे हैं। उनकी प्रारंभिक भूमिका विदेश राज्य मंत्री के रूप में रही। वैश्विक कूटनीति में उनका अनुभव भारत की विदेश नीति को धार देने में उपयोगी सिद्ध हुआ। आज वे भारतीय संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति से जुड़े प्रमुख नेता हैं। इसका कारण है—विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर उनकी गहरी पकड़।

थरूर केवल राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि बहुप्रतिभाशाली लेखक भी हैं। वे 25 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं, जिनमें भारतीय इतिहास, औपनिवेशिक विरासत, लोकतांत्रिक समाज और वैश्विक राजनीति जैसे विषय सम्मिलित हैं। उनके लेखन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पढ़ा और सराहा जाता है। इतना ही नहीं, वे समय-समय पर वैश्विक पत्रिकाओं और मंचों पर भारत की दृष्टि और जनता के हितों को स्पष्ट व प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उनकी भाषा पर मजबूत पकड़ और अद्भुत वक्तृत्व-कला उन्हें दूसरों से अलग पहचान दिलाती है। आज जब भारत दुनिया के साथ नए साझेदारी-संबंध बना रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका सशक्त कर रहा है, ऐसे समय में शशि थरूर जैसे नेता नीतिगत लक्ष्यों और जन-हित के बीच विचार-आधारित संतुलन स्थापित करते हैं। वे भारत की लोकतांत्रिक परंपरा और विविधता की रक्षा के प्रबल समर्थक हैं। उनका मानना है कि भारत की शक्ति उसकी बहुलता, उदारता और सांस्कृतिक आत्मा में निहित है। शशि थरूर का जीवन-पथ केवल एक राजनेता की सफलता-कथा नहीं, बल्कि यह संदेश भी है कि ज्ञान, वैश्विक अनुभव, संवेदनशीलता और संवाद की शक्ति द्वारा समाज तथा राष्ट्र के लिए कितना कुछ किया जा सकता है।

जननायक टंट्या भीलः साहस, स्वाभिमान और न्याय का चिरंजीव संदेश

आज की बात

प्रवीण कक्कड़

स्वतंत्र लेखक

भारत के स्वाधीनता संग्राम में अनगिनत नाम हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जिनकी गाथा जंगलों की ख़ामोशी में जन्मी और जनजातीय समाज के हृदयों में अमर हो गई। मालवा–निमाड़ की धरती पर जन्मे जननायक टंट्या भील, जिन्हें आम जनता प्रेम से "टंट्या मामा" कहती है, ऐसे ही अमर नायकों की श्रेणी में आते हैं। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि आदिवासी स्वाभिमान, न्याय, नेतृत्व और सामाजिक अस्मिता की जीवित चेतना थे। आज भी मालवा की मिट्टी, निमाड़ के जंगल, सतपुड़ा की वादियाँ और दक्कन की पहाड़ियाँ टंट्या मामा के कदमों की प्रतिध्वनि का एहसास कराती हैं। 4 दिसंबर, जो मध्य प्रदेश में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, केवल एक ऐतिहासिक तिथि नहीं, बल्कि साहस, नेतृत्व, संघर्ष और आत्म गौरव का पर्व है।

अन्याय के विरुद्ध उठी एक आवाज

टंट्या मामा का जीवन उस दौर में शुरू हुआ जब भील जनजाति पर अंग्रेजी हुकूमत, साहूकारों और जमींदारों के अत्याचार गहराते जा रहे थे। जंगलों पर लगने वाले प्रतिबंध, पारंपरिक आजीविका पर दबाव, भूमि अधिकारों का हनन और प्रशासनिक कठोरता, इन सबने जनजातीय समाज को गहरे घाव दिए थे। इन्हीं परिस्थितियों ने टंट्या मामा को एक सामान्य व्यक्ति से जननायक बना दिया। उनका संघर्ष किसी हिंसक विद्रोह या प्रतिशोध का परिणाम नहीं था। यह उस पीड़ा का प्रतिफल था जो आदिवासी समुदाय ने वर्षों तक सहन की, अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपने अधिकार की रक्षा के लिए वे खड़े हुए।

गुरिल्ला युद्धकला में अप्रतिम दक्ष योद्धा

टंट्या मामा ने गुरिल्ला युद्धनीति में अद्भुत महारत हासिल की थी। वे पहाड़ों, जंगलों और कठिन भूगोल का उपयोग ऐसे करते थे कि अंग्रेजी सैनिक उनसे हमेशा एक कदम पीछे रहते। मालवा–निमाड़, सतपुड़ा और दक्षिण के जंगल उनके रणक्षेत्र थे और आदिवासी समाज उनका परिवार। अंग्रेज उनके लिए बड़ी संख्या में टुकड़ियाँ भेजते रहे, पर मामा अपनी रणनीति, तेज बुद्धि और अद्भुत फुर्ती के कारण बार-बार पकड़ से बाहर रहते। उनकी जीवन-गाथा में उल्लेख मिलता है कि वे अत्याचारियों से धन लूटते और गरीब आदिवासियों में अनाज, नमक और कपड़े बाँट देते, इसी सामाजिक न्याय के कारण जनता ने उन्हें प्यार से "मामा" कहा—एक ऐसा संबोधन जो आज भी गहरे रिश्ते का प्रतीक है।

आदिवासी न्याय और स्वाभिमान का सबसे बड़ा संदेश

टंट्या मामा अन्याय, शोषण, असमानता और अत्याचार के खिलाफ खड़े थे। उनका संदेश तीन मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित था-

नेतृत्व पद से नहीं, साहस और करुणा से जन्मता है।

उन्होंने दिखाया कि नेता वही है जो अपने समुदाय के दुःख को महसूस करे और समाधान के लिए आगे आए।

अधिकार संघर्ष से प्राप्त होते हैं।

टंट्या मामा ने आदिवासी समाज को बताया कि सम्मान भीख नहीं, साहस और सामुदायिक एकजुटता से मिलता है।

संस्कृति और पहचान सबसे बड़ी शक्ति है।

उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि जब तक समुदाय अपनी भाषा, परंपरा, संस्कृति और जमीन पर गर्व नहीं करेगा, तब तक वह बाहरी दमन के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता।

आज के युवाओं के लिए टंट्या मामा का संदेश

समय बदल गया है, पर उनके मूल्य आज भी वही प्रकाश स्तंभ हैं जो वर्तमान युवा पीढ़ी को दिशा देते हैं-

अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ

यदि कहीं असमानता है—सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक—तो खामोश रहने के बजाय साहसपूर्वक आगे आना ही नेतृत्व का पहला कदम है।

समुदाय को साथ लेकर चलो

नेतृत्व कभी अकेला नहीं होता। टंट्या मामा की असली ताकत भील समाज की एकजुटता थी। युवाओं को भी अपने गाँव, समाज, भाषा और संस्कृति से जुड़ना चाहिए।

शिक्षा और कौशल ही आधुनिक हथियार हैं

जिस तरह टंट्या मामा ने गुरिल्ला नीति सीखकर अंग्रेजों को चुनौती दी, आज के युवाओं को तकनीक, ज्ञान, प्रशासनिक कौशल, खेल और उद्यमशीलता को अपना हथियार बनाना होगा।

संस्कृति पर गर्व करो

उनकी शक्ति उनकी संस्कृति थी। यही कारण है कि टंट्या मामा आज भी भील समाज की अस्मिता, सम्मान और गौरव का प्रतीक हैं।

इतिहास से भविष्य तकः टंट्या मामा की विरासत

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएँ यह दर्शाती हैं कि उनका योगदान केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि विकास की वर्तमान यात्रा का आधार भी है। आज आदिवासी युवा खेल, शिक्षा, प्रशासन, सेना, कला और उद्यमिता-हर क्षेत्र में नई पहचान बना रहे हैं। यदि उन्हें सही अवसर, संसाधन और मार्गदर्शन मिले तो वे समाज के लिए वही ऊर्जा बन सकते हैं जो टंट्या मामा थे।

साहस का वह प्रकाश जो कभी मंद नहीं पड़ता

टंट्या मामा केवल अतीत के नायक नहीं। वे वर्तमान का मार्गदर्शन और भविष्य की प्रेरणा हैं। उनकी गाथा हमें बताती है- कि अन्याय से लड़ना ही नहीं, बल्कि अपने समुदाय के लिए खड़ा रहना भी वीरता है। 04 दिसंबर केवल एक स्मृति का दिन नहीं, यह संकल्प का दिन है कि आदिवासी समाज का उत्थान ही मध्य प्रदेश की असली शक्ति है और साहस, स्वाभिमान और न्याय की वह ज्योति आज भी उतनी ही तेज है जितनी टंट्या मामा के समय थी।

मानसिक गुलाम बनाने वाली मैकाले की शिक्षा पर लगेंगे ताले

प्रमोद भार्गव

वरिष्ठ पत्रकार

'1835 से भारत में पैठ जमा चुकी उस पश्चिमी मानसिकता पर ताले लगाने के राष्ट्रीय संकल्प की जरूरत है, जो स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को ध्वस्त करती हुई औपनिवेशिक शिक्षा को लागू करने की थॉमस मैकाले की परियोजना के माध्यम से लागू हुई थी। भारत की शैक्षिक और सांस्कृतिक नींव को खोखला करने के लिए मैकाले द्वारा किए गए अपराध को 2035 में 200 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अतएव आने वाले दस सालों में गुलामी की इस औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होने के राष्ट्रीय संकल्प की जरूरत है।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये विचार एक्सप्रेस समूह के संस्थापक रामनाथ गोयनका की स्मृति में दिए व्याख्यान में व्यक्त किए थे।

फिरंगी हुकूमत के दौरान इंग्लिश एज्युकेशन एक्ट- 1835 के तहत भारत में संस्कृत, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं की शिक्षा नष्ट कर अंग्रेजी शिक्षा की बुनियाद रखी गई थी। इस दासता को 190 वर्ष से हम ढोते चले आ रहे हैं। अतएव अब इससे मुक्ति का समय आ गया है।

मैकाले की एक किताब है 'द लाइफ एंड लैटर्स ऑफ लार्ड मैकाले'। इस किताब में मैकाले ने भारत की अंग्रेजी शिक्षा पद्यति लागू करते हुए तीन भविष्यवाणियां की थीं, जो खरी उतरीं। उनकी पहली भाष्यवाणी थी कि मेरी इस नई शिक्षा प्रणाली के चलते डेढ़ सौ साल बाद भारतीय व्यक्ति अपने धर्म से विमुख हो जाएगा। उसके घर में अपने धर्म ग्रंथ होंगे, लेकिन वे उन्हें पढ़ेंगे नहीं। दूसरी भविष्यवाणी है, उसे अपनी भाषा बोलने में असुविधा होगी। वह शर्म महसूस करेगा। वह अपनी भाषा में बोल नहीं पाएगा। दूसरी भाषाओं के शब्द उधार लेने पड़ेंगे। तीसरी है, भारतवासी अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनना भूल जाएंगे। पुरुष अपनी वेशभूषा लगभग भूल गए हैं। महिलाएं जरूर अपनी परंपरा को बनाये रखे हुए हैं। याद रहे जिस देश के वासी अपनी भाषा, धर्म और वेशभूषा भूल जाते हैं, उनकी संस्कृति भी धीरे-धीरे नष्ट हो जाती है।लेकिन हम हैं कि अपनी संस्कृति के पराभव से निश्चिंत हैं। अतएव प्रधानमंत्री के संकल्प में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है।

इस परिप्रेक्ष्य में मार्क्सवादी वामपंथी सोच के शिक्षाविद्, इतिहासज्ञ एवं साहित्यकार भी गुलाम भारत में थोपी हुई शैक्षिक रूढ़ियों को एक जन्मजात संस्कार की तरह ढोते रहे हैं। नेहरू मंत्रिमंडल के आरंभिक केंद्रीय शिक्षा मंत्रियों ने इस विचार का बढ़-चढ़कर पोषण किया। इसी का परिणाम रहा कि फिरंगी दासता से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत राष्ट्र की लुप्त कर दी गई सांस्कृतिक संपदा के महत्व को अंगीकार करते हुए ज्ञान, कर्म, संस्कार, भाषा, संस्कृति और कौशल दक्षता को विद्यार्थी में विकसित करने का काम मातृभाषाओं में शिक्षा के माध्यम से कर दिया है। लेकिन शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम से विद्यार्थी को शिक्षित करने की आम भारतीय की गुलाम मानसिकता अभी भी बनी हुई है। इसीलिए देखने में तो शिक्षित भारतवासी भारतीय हैं, किंतु उनके मन में मानसिक गुलामी आज भी बनी हुई है। व्यक्तित्व निर्माण की यही बाधा व्यक्ति में राष्ट्रबोध का पूर्णतः प्रादुर्भाव नहीं कर पा रही है। अतएव दासता के इस शैक्षिक निर्मूलन से मूल्य-बोध के संस्कारों से सांस्कृतिक चेतना का लोकव्यापीकरण होगा और सनातन मानवीय मूल्यों की सुरक्षा के साथ भारतीय भाषाएं भी अपना अस्तित्व बनाए रखेंगी। ये मूल्य न केवल व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि देश को भी आत्मनिर्भरता के शिखर पर पहुंचाएंगे। देश की सांस्कृतिक संप्रभुता की पहचान को भी अक्षुण्ण बनाए रखने का काम करेंगे।

भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के बाद एक समय तक अंग्रेजों की भाषा-नीति में बदलाव होता रहता था। सन् 1833 में मैकाले मिनिट्स के होते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अदालती तथा अन्य शासकीय कार्यों में अरबी-फारसी का मिश्रित रूप अपनाया था। हिंदू राजाओं के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पत्र-व्यवहार में स्थानीय बोलियों के शब्दों का भी प्रयोग करती थी।किंतु 1835 में इंग्लिश एज्युकेशन एक्ट लागू होने के बाद से स्थितियां बदलती चली गईं। हालांकि 1880 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। उस समय अंग्रेजी शासन की राजधानी कोलकाता थी। जॉन गिलक्राइस्ट उस कॉलेज के भाषा विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने खड़ी बोली के प्रयोग को प्रोत्साहित किया और कंपनी सरकार की भाषा नीति तय करने में आवश्यक सुझाव दिए। वह हिंदी को हिंदुई तथा हिंदुस्तानी कहते थे और उसके लिए रोमन लिपि को आवश्यक मानते थे, किंतु न तो हिंदी का नाम बदल सके और न ही लिपि।

गिलक्राइस्ट के बाद ही, मैकाले की भाषा-नीति मानी गई और उच्च शिक्षा से संस्कृत एवं हिंदी का माध्यम समाप्त कर दिया गया। वैदिक संस्कृत, गणित एवं समाज विज्ञान की शिक्षाओं को धार्मिक शिक्षा की श्रेणी में रखकर नकार दिया गया। उन्नीसवीं शताब्दी के चौथे दशक में सरकारी कामकाज में उर्दू को वरीयता दी गई और हिंदी को उपेक्षित कर दिया गया। उस युग में बनारस हिंदी का केंद्र था और बनारस की दो बड़ी हस्तियां हिंदी में लिख रहीं थीं। एक थे राजा शिवप्रसाद और दूसरे भारतेंदु हरिशचंद्र। राजा शिवप्रसाद अंग्रेजी सरकार की सेवा में थे और अंग्रेजों की भाषा नीति का समर्थन करते हुए उन्होंने उर्दू का पक्ष लेते हुए हिंदी की निंदा की। उनकी वफादारी देखकर सरकार ने उन्हें 'सितारे हिंद' की उपाधि दी। हरिश्चंद्र ने सरकार की भाषा-नीति का विरोध किया और जगह-जगह जाकर हिंदी के समर्थन में सभाएं कीं। जनता ने हरिश्चंद्र को 'भारतेंदु' की उपाधि से विभूषित किया। भारतेंदु की लोकप्रियता के सामने सितारे हिंद अस्त-पस्त हो गए। जॉन गिलक्राइस्ट जैसे अनेक अंग्रेज हिंदी के समर्थक थे। ऐसे अंग्रेजों में हेनरी पिनकोट ने भारतेंदु के समर्थन में हिंदी के पक्ष में बहुत काम किया। राजा शिवप्रसाद की तरह राजा लक्ष्मण सिंह (1826-96) भी सरकारी नौकर थे, किंतु उन्होंने हिंदी का समर्थन किया और उसी में लिखा भी। इस दौरान देश में जो विवि और राज्य स्तरीय शिक्षा मंडल अस्तित्व में आए, उन्होंने अंग्रेजी विषयक पाठ्यक्रमों में आंग्ल साहित्य का अध्ययन, अध्यापन बीसवीं सदी की शुरूआत में ही कर दिया था। इस समय भारतीय लेखक जो भी कुछ अंग्रेजी में लिख रहे थे, उसे पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाता था। इनमें ज्यादातर लेखक बंगाली थे और इन पाठ्यक्रमों की शुरुआत भी बंगाल में हुई। इन लेखकों की लिखने की पद्धति लगभग अंग्रेजियत में सराबोर थी। चारण-भाटों की शैली में इन्होंने अंग्रेजी का स्तुतिगान तो किया ही, तात्कालिक लाभ के लिए इनमें से कई क्रिश्चियन भी बन गए। नौकरी के लिए मतांतरण की शुरुआत यहीं से हुई। भारत की धरती पर अंग्रेजी का बीज बोने और इसे उर्वरा बनाने के पैरोकार मैकाले ने ऐसे लोगों को वजीफे दिलाए और लंदन की मुफ्त में सैर भी कराई। सही मायनों में ये तथाकथित अंग्रेजी के लेखक इंग्लैंड के बंधुआ साहित्यकार थे। इन्होंने अंग्रेजी के प्रभुत्व को स्थापित करने के उपायों के साथ विस्तार के मार्ग भी प्रशस्त किए। इनमें तोरु दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त और मनमोहन घोष प्रमुख थे। गोया, ब्रिटिश हुक्मरानों के भय के चलते इन बंधुआओं से लेखन में भारतीयता का प्रभाव डालने की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती थी।

जिस राष्ट्रीय चेतना को हम स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में लेते हैं, उस तरह के लेखन का भारतीय अंग्रेजी लेखकों में सर्वथा अभाव था। हालांकि 'वंदे मातरम' गीत के रूप में भारत को उसकी व्यापक राष्ट्रीयता की पहचान देने वाले बांग्ला उपन्यासकार बंकिमचंद्र चटर्जी न केवल बंगाल के चुनिंदा लेखकों में से एक थे, बल्कि उन्हें भारतीय अंग्रेजी साहित्य के शुरूआती लेखन का श्रेय भी जाता है। उन्होंने 'राजमोहन वाइफ' उपन्यास अंग्रेजी में लिखा था। किंतु राष्ट्रीय स्वाभिमान के चलते कालांतर में उन्होंने केवल बांगला और संस्कृत में लिखने का संकल्प लिया। अंग्रेजी में रचना-सृजन पर पूरी तरह विराम लगा दिया। भाषाई अस्मिता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रकल्प का यह ऐसा अनूठा संकल्प था, जिसने वंदे मातरम के माध्यम से फिरंगी सत्ता को चुनौती देते हुए जनमानस में सर्वाधिक राष्ट्रबोध जगाने का काम किया।

आर्थिक उदारवादी नीतियां लागू होने के बाद देश में आवारा पूंजी का दबाव इस हद तक बढ़ा कि हम पूंजी आधारित लिप्सा और औपनिवेशिक शक्तियों की व्यवस्था को विकास व प्रगति का आदर्श मानक मानने लगे। नतीजतन आर्थिक विषंगति बढ़ी और असंतोष उपजा। माओवाद बनाम नक्सलवाद की जड़ें गहरी करने में इस असंतोष ने उर्जा का काम किया। वामपंथी चरमपंथ ने इस असंतोष को अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए भुनाने का काम किया। समरसता व समावेशन संबंधी जो मूल अवधारणाएं हैं, उन्हें इस चरमपंथ ने समूल नष्ट करते हुए वर्ग संघर्ष पैदा करने का काम किया। विषमता और वैमनस्यतापूर्ण समाज-रचना को बढ़ावा दिया। भावनात्मक इस विद्वेश ने स्वतंत्र वैचारिक मानसिकता को कुंठित करने का काम किया। जबकि विचार-निर्माण के लिए शैक्षिक परिसरों में लोकतांत्रिक खुलेपन की जरूरत है, जिससे शिष्य, शिक्षक से प्रश्न करने में कोई संकोच न करे। दुर्भाग्य से हमने आज्ञाकारी शिष्य को आदर्श माना हुआ है। यह आज्ञाकारिता नव-सृजनशीलता के लिए बाधक है। यही कारण है कि हम नवोन्वेष, वैज्ञानिक अनुसंधान और देशज उत्पादकता में लगातार पिछड़ते जा रहे थे, इसमें अब मोदी के नेतृत्व में गति आ रही है।

हमारी पूरा शिक्षाजन्य ढांचा, आज्ञापालन को प्रोत्साहित व पुरस्कृत करता है। स्वातंत्र्य-चेता विद्यार्थी की नूतन पहल, जिज्ञासा और प्रश्नाकूलता को फटकारा जाता है। विचार नियंत्रण की यह क्रूरता नव-सर्जक की भ्रूण-हत्या कर देती है। यही कारण है कि हम आजादी के बाद न तो नचिकेता, अष्टावक्र और विवेकानंद पैदा कर पाए और न ही सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु और रामानुजन? दरअसल औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति और अंग्रेजी की अनिवार्यता के चलते हमारे शिक्षा संस्थान महज डिग्रीधारी नकलचियों की फौज खड़ी करने में लगे हैं। वे रोबोट और क्लोन बनाने की दक्षता को ही श्रेष्ठता का पर्याय मानकर चल रहे हैं, क्योंकि रोबोट विरोध नहीं करते और क्लोन से विकसित प्राणी प्रकृति प्रदत्त विलक्षणता खो देते हैं, अतएव उनकी मौलिक सृजनशीलता बचपने में ही कुंठित हो जाती है। आज्ञापालकों के ये उत्पाद अंततः सृजन से जुड़ी वैचारिकता के लिए आघातकारी सिद्ध होते हैं, केवल कैरियर बनाना और पैसा कमाना इनका मुख्य ध्येय रह जाता है, जो व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं। नरेंद्र मोदी ने अब आने वाले 10 साल में मैकाले की शैक्षिक एवं अंग्रेजी मानसिकता से मुक्ति का जो संकल्प लिया है, उससे जरूर बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।

दिल्ली की सरकार बदली लेकिन हवा नहीं

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

दिल्ली में सरकार बदलने के बाद उम्मीद थी कि इस साल प्रदूषण में कमी आएगी लेकिन कम होने के बजाय वायु की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं है। लोग दिल्ली को छोड़ने पर मजबूर है। डॉक्टर लोगों को दिल्ली छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। यमुना की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली की सरकार पूर्ववत सरकारों की तरह न तो नदियों की भाषा और आवाज़ सुन पा रही है न हवा की दिशा और दशा समझ पा रही है। पहले की सरकार पराली को दोषी ठहराती रही लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की जहरीली हवा का असली विलेन ट्रैफिक और स्थानीय कारक है, पराली का धुआं नहीं। इस बार दिल्ली के वायु प्रदूषण में पराली के धुएं का योगदान पांच प्रतिशत से भी कम हुआ, फिर भी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के पहले हफ्ते में ज्यादातर दिन AQI लगातार बेहद खराब और "गंभीर" में बना रहा। यह प्रदूषण मौसम की देन नहीं है बल्कि विस्मृति का नतीजा है। सरकार और नागरिक दोनों के उदासीनता का नतीजा है। सरकारी विभागों की लापरवाही के कारण भी दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन सड़कों की सफाई और धूल कंट्रोल के उपायों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के इंस्पेक्शन के अनुसार, सबसे खराब हालत दिल्ली नगर निगम की सड़कों पर है। ज्यादातर सड़कों पर धूल उड़ रही है। CAQM ने हालात सुधारने के निर्देश दिए हैं। लोगों को भी समझना चाहिए कि प्रदूषण कम करना सिर्फ सरकार का काम नहीं है बल्कि जनता का भी है। मंत्री, नेता, सरकारी अधिकारी के साथ साथ सभी लोगों को अपनी निजी गाड़ियों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय भी इसपर बहुत गंभीर है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण संकट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायधीश ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा बनाए गए दीर्घकालिक योजनाएं भी सार्वजनिक की जाए। विडंबना यह है कि कोई भी राजनीतिक दल इसके प्रति गंभीरता नहीं दिखाती। तभी तो यह समस्या वर्षों से खड़ी है। केवल वे आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। प्रदुषण खत्म करने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं लेकिन परिणाम कुछ नही निकलता। सभी राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि हवा धर्म, जाति, सीमा आदि नही देखती। यह जहरीली हवा सबके लिए खतरनाक है।

वायु प्रदूषण जहर का काम कर रहा है जो धीरे धीरे मनुष्य के शरीर को क्षति पहुंचाता हुआ उम्र को कम करता जा रहा है। गंदी हवा गैसों और कणों का जटिल मिश्रण है। PM 2.5 कण जिनमे से कुछ इतने छोटे होते हैं कि वे रक्त प्रवाह मे चले जाते है जो बहुत घातक होते हैं। इसका असर शरीर के विभिन्न प्रणाली को प्रभावित करता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लंबे समय तक सम्पर्क में रहने से संज्ञात्मक गिरावट हो सकती है। मस्तिस्क की संरचना मे मे परिवर्तन से अल्जाइमर रोग का खतरा बढ़ जाता है। हृदय प्रणाली, तंत्रिका प्रणाली, श्वसन प्रणाली, गुर्दे की प्रणाली, प्रजनन प्रणाली इत्यादि को वायु प्रदूषण प्रभावित करता है। इस प्रदूषण से जान का नुकसान ही नही हो रहा है। माल का भी नुकसान हो रहा है। देश भर में वायु प्रदूषण से अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ रहा है। वायु प्रदूषण एवं पर्यावरण सम्बन्धित समास्याओं को समझने, विश्लेषण करने और समाधान के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जनता सभी में जागरूकता की आवश्यकता है। इसके लिए तत्काल गंभीर कदम उठाने होंगे वरना आने वाले सालों में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा।

पुनर्वास से सशक्तिकरण : एम्स भोपाल ने विश्व दिव्यांग दिवस पर दिया स्वावलंबन का संदेश

-समता पाठक

जगत प्रवाह. भोपाल। एम्स भोपाल के भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग (PMR) द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस एवं विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर 03 दिसंबर 2025 को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजन और उनके परिवारों को पुनर्वास सेवाओं, सहायक उपकरणों और सरकारी योजनाओं के बारे में सरल एवं उपयोगी जानकारी प्रदान करना था। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) माधवानंद कर ने कहा कि पुनर्वास चिकित्सा बीमारी या दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन में लौटने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मजबूत इच्छाशक्ति से जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। मेडिकल सुपरिन्टेंडेंट प्रो. (डॉ.) विकास गुप्ता ने PMR विभाग की प्रगति को सराहनीय बताते हुए कहा कि विभाग ने सेवाओं, उपचार पद्धतियों और सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिससे मरीजों को बेहतर और प्रभावी पुनर्वास सहायता मिल रही है। इस कार्यक्रम में प्रो. (डॉ.) रजनीश जोशी (डीन एकेडेमिक्स), डॉ. विठ्ठल प्रकाश पुरी (सह-प्राध्यापक, PMR), डॉ. अनुराधा दिवाकर शेनॉय (सहायक प्राध्यापक, PMR) और डॉ. जॉन संतोषी (प्रोफेसर, ऑर्थोपेडिक्स) सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। सांस्कृतिक प्रस्तुति के तहत सुश्री माया कुमारी शर्मा (सीनियर नर्सिंग ऑफिसर) ने विश्व विकलांग दिवस पर एक प्रेरणादायक कविता प्रस्तुत की। ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेक्शन में मरीजों एवं परिजनों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। श्रीमती भूमि भागवतकर (व्यावसायिक चिकित्सक) ने सहायक उपकरणों का प्रदर्शन किया और बताया कि किस प्रकार इनसे दिव्यांगजन अपने दैनिक कार्यों में अधिक स्वावलंबी बन सकते हैं। श्रीमती सपना मौर्य (व्यावसायिक परामर्शदाता) ने दिव्यांगजन के लिए सरकारी योजनाओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी, जिससे लोगों को यह समझने में मदद मिली कि वे इन योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं। अंत में विजेताओं को स्मृति चिन्ह, पुरस्कार और मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अंकिता वाडनेकर (फिजियोथैरेपिस्ट) ने किया।

महाकौशल शुगर मिल विवाद : जमीन मालिक ने आरोपों को नकारा, मिल संचालक पर भटकाने का आरोप

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले के बचई स्थित महाकौशल शुगर मिल विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। मिल संचालक नवाब रज्जा द्वारा मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल पर लगाए गए दबाव और तुलाई केंद्र बंद कराने के आरोपों को अब जमीन मालिक ने सिरे से खारिज कर दिया है। एक प्रेस वार्ता में तुलाई केंद्र की जमीन के मालिक रविन्द्र पटेल ने कहा कि नवाब रज्जा सच्चाई से दूर हैं और बिना जानकारी के मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर भटका रहे हैं। भूमि विक्रय का इकरारनामा प्रस्तुत करते हुए रविन्द्र पटेल ने बताया कि उन्होंने संबंधित जमीन अक्टूबर माह में ही बेचने का समझौता किया था। यह भूमि उनकी पुत्री प्रज्ञा पटेल (34 वर्ष) के नाम दर्ज है और इसे करेली निवासी अजीत सिंह छाबड़ा को बेचा जा चुका है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया अभी शेष है। उन्होंने जानकारी दी कि यह भूमि मौजा उमरिया, तहसील करेली में खसरा नंबर 422/1(S), 422/2(S), 421/1(S) और 431/3 पर स्थित है, जिसका कुल रकबा 0.891 हेक्टेयर (2 एकड़ 3 डिसमिल) है। यह भूमि व्यावसायिक उपयोग के लिए डायवर्टेड है और इसका सौदा 52 लाख रुपए में तय हुआ है, जो दस्तावेजों में दर्ज है। रविन्द्र पटेल ने इन आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने नवाब रज्जा को सलाह दी कि वे षड्यंत्र का हिस्सा न बनें और अपने व्यापार पर ध्यान दें, बजाय इसके कि वे अनावश्यक राजनीति में पड़ें। पटेल ने कहा कि नवाब रज्जा या तो बड़ी छलांग लगाने की सोच रहे हैं या भयभीत और आशंकित हैं, और वे उतने भोले नहीं हैं जितना दिखाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि नवाब रज्जा द्वारा लगाए गए आरोप न केवल तथ्यहीन हैं, बल्कि उनकी और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल तथा पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल की छवि को नुकसान पहुंचाने की सोची-समझी कोशिश है। रविन्द्र पटेल ने घोषणा की कि वह इस मामले में मिल संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

सिंहस्थ क्षेत्र से लैंड पुलिंग कानून निरस्त करे सरकार अन्यथा भारतीय किसान संघ करेगा प्रदेशव्यापी आंदोलन

-शिवमोहन सिंह

जगत प्रवाह. भोपाल। भारतीय किसान संघ मध्यप्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई। जिसमें किसान संघ ने मांग की कि क्षेत्र से लैंड पुलिंग कानून सरकार तत्काल निरस्त करने का गजट नोटिफिकेशन सरकार जारी करे, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापिस करे, टीडीएस की धारा 8/9/10/11 के गजट नोटिफिकेशन रदद हों, सिंहस्थ क्षेत्र में स्थाई निर्माण न किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने रोष व्यक्त करते हुए आगे कहा कि सात दिन के भीतर यदि सरकार ये मांगे नहीं मानती है तो भारतीय किसान संघ लैंड पुलिंग कानून के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा। जिसमें प्रदेश भर से हजारों किसान उज्जैन आयेंगे। जिसकी तिथि शीघ्र घोषित होगी। बैठक में सभी प्रांतों के अध्यक्ष, महामंत्री व संगठन मंत्री को आंदोलन की तैयारी के लिए प्रांत, जिला, तहसील, ग्राम समिति में बैठके आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)